ISSN: 2278-4632
Vol-16, Issue-03, 2026

ग्रामीण कृषि आर्थिकी, वित्तीय समावेशन एवं तकनीकी अंगीकरण में संचार क्रांति: पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समाजशास्त्रीय समीक्षा

सुश्री तृप्ति सिंह
शोधार्थी (समाजशास्त्र)
समाजशास्त्र विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)
एवं
डॉ जनक बहादुर
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

शोध सारांश

प्रस्तुत समीक्षात्मक शोध पत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद देवरिया के डॉक्टरेट समंकों के आधार पर कृषि आर्थिकी, वित्तीय समावेशन व तकनीकी नवाचार अंगीकरण में संचार क्रांति की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करता है। पारंपरिक समाज में सूचना विषमता के कारण छोटे किसान बिचौलियों के शोषण के शिकार थे। 4G/5G स्मार्टफोन (89.42%) क्रांति ने इस गतिरोध को तोड़ा है। समंक दर्शाते हैं कि 92.37% कृषक पीएम-किसान डीबीटी से जुड़े हैं, 77.97% किसान मौसम ऐप्स से प्रति सीजन ₹3,000-₹6,000 की बचत कर रहे हैं, तथा 65.25% किसान डिजिटल मंडी भावों की निगरानी से लाभान्वित हैं। वित्तीय स्तर पर 93.27% परिवारों के जनधन खाते, 69.23% द्वारा AePS तथा 66.35% द्वारा यूपीआई के नियमित उपयोग ने पारंपरिक साहूकारी व्यवस्था (60-120% ब्याज) को समाप्त कर दिया है। कार्ल पियर्सन सहसंबंध तथा काई-वर्ग ($\chi^2 = 48.32$, $df = 4$, $p < 0.001$) द्वारा संचार उपभोग और कृषि-वित्तीय सजगता में उच्च सार्थक धनात्मक संबंध पुष्ट हुआ। हालांकि, टैरिफ वृद्धि (71.15% पर बोझ), कमजोर सिग्नल (63.46%), तथा साइबर ठगी (16.35% पीड़ित) गंभीर चुनौतियां हैं। पत्र अंत में भारतनेट 3.0, रियायती ग्रामीण डेटा पैक तथा ग्राम साइबर हेल्पडेस्क की नीतिगत संस्तुति करता है।

बीज शब्द : संचार क्रांति, कृषि आर्थिकी, वित्तीय समावेशन, यूपीआई, नवाचार विसरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सूचना विषमता, देवरिया।

1. प्रस्तावना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मानव समाज के सामाजिक-आर्थिक इतिहास में उत्पादन प्रणालियों, विनिमय संबंधों तथा चेतना के विस्तार की धुरी संचार माध्यम रहे हैं (कूले, 1909, पृ. 61)। भारतीय समाज का वास्तविक स्पंदन उसके ग्रामों में रहा है (गांधी, 1942, पृ. 38)। स्वाधीनता के पश्चात दशकों तक ग्रामीण परिवेश सूचना अभाव और सामंती संस्तरण का शिकार रहा। सूचना पर बड़े भूस्वामियों, साहूकारों और आढ़तियों का एकाधिकार था, जिसे जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ (2002, पृ. 460) ने 'सूचना असममिति' कहा है। देवरिया जैसे सीमांत कृषि जनपद में छोटा किसान उन्नत बीजों, उर्वरक प्रबंधन, मौसम की चेतावनियों तथा प्रादेशिक मंडी भावों से अनभिज्ञ रहकर औने-पौने दामों में फसल बेचने को विवश था।

ऐतिहासिक रूप से 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1966 का 'किसान वाणी' रेडियो तथा 1975 का उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग महत्वपूर्ण पहल थे (अग्रवाल, 1981, पृ. 12; सिंघल एवं रोजर्स, 2001, पृ. 78)। तथापि, बीसवीं सदी तक ये माध्यम एकपक्षीय रहे। वास्तविक गुणात्मक छलांग वर्ष 2014 के 'डिजिटल इंडिया' मिशन और 2016 की 4G एलटीई डेटा क्रांति से संभव हुई (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 2022, पृ. 5)। विश्व में सबसे सस्ती डेटा दरों (₹5-₹10 प्रति GB) और किफायती स्मार्टफोन्स ने पूर्वांचल के कृषि परिदृश्य में सूचना महाविस्फोट कर दिया (ट्राई, 2024, पृ. 35)। प्रस्तुत शोध पत्र तृप्ति सिंह (2026) के डॉक्टरेट शोध समंकों के आलोक में कृषि-आर्थिक रूपांतरण की समीक्षा करता है।

Copyright @ 2026 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-16, Issue-03, 2026

2. सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक परिप्रेक्ष्य

कृषि आर्थिकी और तकनीकी अंगीकरण की इस परिघटना को समझने हेतु प्रमुख समाजशास्त्रीय व आर्थिक सिद्धांतों का संश्लेषण आवश्यक है:

1. एवरेट एम. रोजर्स का नवाचार प्रसरण सिद्धांत: रोजर्स (1995, 2003) के अनुसार नवाचार अंगीकरण पांच चरणों—ज्ञान, अनुनय, निर्णय, क्रियान्वयन तथा संपुष्टि—से गुजरता है। अंगीकारकर्ताओं की पांच श्रेणियां—नवाचारी, प्रारंभिक अंगीकारक, प्रारंभिक बहुसंख्यक, उत्तरवर्ती बहुसंख्यक तथा परंपरावादी—होती हैं। नवाचार के पांच गुण (सापेक्षिक लाभ, अनुकूलता, सरलता, परीक्षणशीलता, अवलोकनशीलता) अंगीकरण की गति तय करते हैं। देवरिया में मौसम ऐप्स, ई-गन्ना व यूपीआई का प्रसार रोजर्स के सापेक्षिक लाभ व अनुकूलता को सिद्ध करता है।
2. अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण: सेन (1999, पृ. 87) के अनुसार वास्तविक विकास व्यक्ति की मौलिक क्षमताओं और स्वतंत्रताओं का विस्तार है। सूचना की स्वतंत्रता एक 'साधनात्मक स्वतंत्रता' है जो आर्थिक सुरक्षा व बाजार पारदर्शिता को गति देती है। स्मार्टफोन ने सीमांत किसान की 'सौदाकारी शक्ति' को सुदृढ़ किया है।
3. जोसेफ शुम्पीटर की ग्रामीण उद्यमशीलता: शुम्पीटर (1934, पृ. 65) का 'सृजनात्मक विनाश' बताता है कि नई प्रौद्योगिकियां पुरानी अक्षम प्रणालियों को समाप्त कर नए आजीविका अवसर खोलती हैं। देवरिया के गांवों में सीएससी, मोबाइल रिपेयरिंग तथा डिजिटल दुग्ध संग्रह केंद्र इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।
4. डेनियल लर्नर की 'मानसिक गतिशीलता': लर्नर (1958, पृ. 43) ने आधुनिकीकरण में 'सहानुभूति' और 'मानसिक गतिशीलता' को केंद्रीय माना। दृश्य-श्रव्य डिजिटल माध्यम किसान को नई भूमिकाओं की कल्पना करने में सक्षम बनाते हैं। किसान यूट्यूब पर आधुनिक तकनीकें देखकर स्वयं को प्रगतिशील कृषि उद्यमी में रूपांतरित करता है (सिंह एवं बहादुर, 2024, पृ. 115)।

3. शोध प्रविधि एवं अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत समीक्षा में वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक व विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप का समन्वित प्रयोग हुआ है (कोठारी एवं गर्ग, 2019, पृ. 152)। अध्ययन क्षेत्र देवरिया जनपद का क्षेत्रफल 2,540 वर्ग किमी तथा जनसंख्या 31,00,946 है जिसमें 89.8% (27.81 लाख) ग्रामीण आबादी है (जनगणना कार्य निदेशालय, 2011)। घनत्व 1,221 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है जो जोतों के विखंडन को दर्शाता है। खाड़ी देशों में भारी प्रवासन के कारण लिंगानुपात 1,017 है।

विलियम जी. कोचरन (1977, पृ. 72) के सूत्र $n_0 = (Z^2 \cdot p \cdot q) / e^2$ द्वारा 95% विश्वास स्तर व 4.8% त्रुटि सीमा पर N = 416 का प्रतिदर्श तय हुआ। बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन से चार विकास खंड—देवरिया सदर (मुख्यालय/अर्ध-ग्रामीण), बरहज (घाघरा-राप्ती कछार), भटनी (बिहार सीमावर्ती/प्रवासन), तथा रुद्रपुर (पारंपरिक संरचना)—चुने गए। प्रत्येक ब्लॉक से 4 ग्राम पंचायतें (कुल 16 पंचायतें) व प्रत्येक से 26 उत्तरदाता (प्रति ब्लॉक 104, कुल N = 416) चयनित हुए। प्रतिदर्श में 220 पुरुष (52.88%) व 196 महिलाएं (47.12%) थीं। साक्षात्कार अनुसूची की विश्वसनीयता का क्रोनबैक अल्फा $\alpha = 0.842$ प्राप्त हुआ (क्रोनबैक, 1951)।

सारणी 1: उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

क्र.	सामाजिक-आर्थिक आयाम	श्रेणी/संवर्ग	आवृत्ति (f)	प्रतिशत (%)
1	सामाजिक संवर्ग (जाति)	अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग	228 94 94	54.81% 22.60% 22.60%
2	आयु संरचना	18-30 वर्ष (युवा) 31-45 वर्ष (प्रौढ़) 46-60 वर्ष (अधेड़)	182 156 58	43.75% 37.50% 13.94%

Copyright @ 2026 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-16, Issue-03, 2026

		60+ वर्ष (वरिष्ठ)	20	4.81%
3	शैक्षणिक स्तर	निरक्षर प्राथमिक/पूर्व-माध्यमिक माध्यमिक/इंटरमीडिएट स्नातक व उच्च शिक्षा	52 88 164 112	12.50% 21.15% 39.42% 26.92%
4	मुख्य पारिवारिक व्यवसाय	कृषि एवं काश्तकारी खेतिहर मजदूरी व श्रम घरेलू कार्य (ग्रामीण गृहिणी) ग्रामीण व्यापार/कारीगरी शासकीय/प्रवासी सेवा	168 68 92 48 40	40.38% 16.35% 22.12% 11.54% 9.62%
5	भूमि जोत का आकार (कुल कृषक n=196)	सीमांत कृषक (< 1 हेक्टेयर) लघु कृषक (1-2 हेक्टेयर) मध्यम व बड़े (> 2 हे.) भूमिहीन दैनिक मजदूर	118 50 28 68	28.37% (60.20% कृषक) 12.02% (25.51% कृषक) 6.73% (14.29% कृषक) 16.35% (समग्र में)
6	पारिवारिक मासिक आय	< ₹5,000 (अति निर्धन) ₹5,001 - ₹15,000 (निम्न मध्यम) ₹15,001 - ₹30,000 (मध्यम) > ₹30,000 (उच्च मध्यम/प्रवासी)	68 184 116 48	16.35% 44.23% 27.88% 11.54%

स्रोत: प्राथमिक समंक, तृप्ति सिंह (2026), पी.के. विश्वविद्यालय शोध प्रबंध।

4. अनुभवजन्य समंक विश्लेषण एवं समाजशास्त्रीय विमर्श

4.1 उपकरणों का स्वामित्व एवं डिजिटल अवसंरचना

सर्वेक्षण दर्शाता है कि स्मार्टफोन ग्रामीण जीवनयापन का बुनियादी औजार बन चुका है। कुल 416 उत्तरदाताओं में से 89.42% (372 उत्तरदाता) के पास सक्रिय स्मार्टफोन उपलब्ध पाया गया। इसके विपरीत रंगीन टीवी 75.00% तथा डीटीएच 64.42% परिवारों में उपलब्ध थे। रेडियो मात्र 11.54% तथा साधारण कीपैड फोन केवल 10.58% के पास शेष बचा है, जिनका उपयोग मुख्यतः 60+ वर्ष के वृद्ध करते हैं। कंप्यूटर/लैपटॉप का स्वामित्व मात्र 8.65% तक सीमित था, जो सिद्ध करता है कि ग्रामीण अंचल ने पीसी युग को लांघकर सीधे स्मार्टफोन इंटरनेट तंत्र को अपना लिया है (जेफरी एवं डोरन, 2013, पृ. 45)। 77.88% उत्तरदाता नियमित 1.5 से 2 GB दैनिक डेटा पैक का उपभोग करते हैं। ऐप्स में व्हाट्सएप (88.46%) तथा यूट्यूब (85.58%) शीर्ष पर हैं, जिसके बाद यूपीआई (66.35%) व ई-गवर्नेंस (47.60%) हैं।

4.2 कृषि सूचना प्रणाली एवं मौसम पूर्वानुमान प्रबंधन

सक्रिय कृषकों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि 77.97% किसान (184 कृषक) 'मेघदूत' व बुलेटिन से 5-दिवसीय ब्लॉक-स्तरीय पूर्वानुमान नियमित प्राप्त कर रहे हैं (मौसम विज्ञान विभाग, 2021)। 82% किसानों ने स्वीकार किया कि वे निजी नलकूपों से सिंचाई प्रारंभ करने से पूर्व मौसम ऐप जांचते हैं; 24-48 घंटों में वर्षा की 70% संभावना पर वे ₹1,500-₹2,000 प्रति एकड़ की डीजल सिंचाई रोक देते हैं, जिससे प्रति किसान प्रति सीजन ₹3,000-₹6,000 की सीधी बचत होती है। इसके अतिरिक्त, 'दामिनी' ऐप (38% फोन में सक्रिय) ने आकाशीय बिजली की 30-45 मिनट पूर्व चेतावनी देकर जान-माल की रक्षा की है (आईआईटीएम, 2022)। 68.27% किसान स्मार्टफोन से फसल की तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप समूहों पर भेजते हैं और केवीके वैज्ञानिकों से 24 घंटे में प्रामाणिक उपचार नुस्खा प्राप्त करते हैं।

4.3 शासकीय कृषि योजनाएं, ई-गन्ना एवं पारदर्शी मूल्य संवर्धन

Copyright @ 2026 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-16, Issue-03, 2026

शासकीय योजनाओं में पीएम-किसान सम्मान निधि के प्रति 92.37% (218 कृषक) की सार्वभौमिक जागरूकता पाई गई। ₹2,000 की समयबद्ध किस्त ने बुवाई समय खाद-बीज क्रय में साहूकारों से मुक्ति दिलाई है (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, 2022)। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के प्रति 60.17% (142 किसान) जागरूक थे, जिससे यूरिया के असंतुलित उपयोग में 20-25% कमी और प्रति एकड़ ₹800-₹1,200 की बचत हुई। 'गन्ने के कटोरे' देवरिया में पूर्व में 'गन्ना माफिया' व घटतौली आम थी। उत्तर प्रदेश सरकार के 'ई-गन्ना' ऐप से 100% गन्ना किसान जुड़े हैं, जहां सट्टा कैलेंडर, पर्ची, तौल वजन व बैंक भुगतान पारदर्शी हुआ है (गन्ना विकास विभाग उ.प्र., 2023)। 'एगमार्कनेट' से 65.25% किसान प्रतिदिन सुबह 9 बजे थोक भाव देखकर आढ़तियों से मजबूत मोलभाव करते हैं, जिससे औने-पौने दामों में फसल बेचने में 40% से अधिक की कमी आई है।

4.4 ग्रामीण वित्तीय समावेशन एवं कैशलेस क्रांति

जनधन, डीबीटी तथा यूपीआई व AePS की त्रिमूर्ति ने ग्रामीण बैंकिंग का कायाकल्प कर दिया है (वित्त मंत्रालय, 2021; एनपीसीआई, 2024)। सारणी 2 में वित्तीय साधनों का विवरण प्रस्तुत है:

सारणी 2: वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल भुगतान माध्यमों का उपभोग

क्र.	वित्तीय समावेशन एवं भुगतान साधन	सक्रिय उपयोक्ता (f)	प्रतिशत (%)	समाजशास्त्रीय प्रभाव एवं उपादेयता
1	प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाता	388	93.27%	सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच; महिलाओं के नाम स्वतंत्र खाते व वित्तीय दृश्यता
2	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	374	89.90%	गैस सब्सिडी, पीएम-किसान, छात्रवृत्ति; बिचौलियों व कमीशनखोरी का पूर्ण अंत
3	आधार सक्षम भुगतान प्रणाली	288	69.23%	अंगूठा लगाकर दरवाजे पर नकद निकासी; 5-10 किमी बैंक यात्रा व कतारों से मुक्ति
4	सक्रिय यूपीआई	276	66.35%	किराना, खाद-बीज क्रय, मोबाइल रिचार्ज; नकदी-रहित पारदर्शी सूक्ष्म लेन-देन
5	मोबाइल बैंकिंग ऐप	142	34.13%	स्टेटमेंट, एफडी, बड़ा फंड ट्रांसफर; शिक्षित युवा, व्यवसायी व प्रवासी परिवार

स्रोत: प्राथमिक समंक, तृप्ति सिंह (2026), पी.के. विश्वविद्यालय शोध प्रबंध।

समंक सिद्ध करते हैं कि 93.27% परिवारों का औपचारिक बैंकिंग से जुड़ना तथा 89.90% का डीबीटी प्राप्त करना कल्याणकारी राज्य की सीधी पहुंच का प्रमाण है। डीबीटी ने रिसाव को समाप्त किया है। सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन यह हुआ कि गांव के पारंपरिक सूदखोर महाजनों की 60-120% वार्षिक ब्याज वाली शोषणकारी व्यवस्था टूट चुकी है। अब किसान आकस्मिक आवश्यकता पर जनधन ओवरड्राफ्ट, केसीसी, एसएचजी ऋण अथवा खाड़ी से यूपीआई द्वारा त्वरित पैसे प्राप्त कर लेते हैं।

5. शोध परिकल्पना (H_1) का सांख्यिकीय परीक्षण एवं सत्यापन

शोध प्रबंध की प्रथम परिकल्पना का परीक्षण किया गया:
• परिकल्पना कथन (H_1): "ग्रामीण उत्तरदाताओं के संचार साधनों के उपयोग की आवृत्ति और उनकी कृषि एवं आजीविका संबंधी जागरूकता के मध्य सार्थक धनात्मक सहसंबंध है।"

Copyright @ 2026 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-16, Issue-03, 2026

• *शून्य परिकल्पना (H_{01}): "ग्रामीण उत्तरदाताओं के संचार उपयोग की आवृत्ति तथा कृषि जागरूकता के मध्य कोई सार्थक सांख्यिकीय संबंध नहीं है।"*

स्वतंत्र चर को स्क्रीन समय, डेटा पैक, ऐप उपयोग व नियमितता के आधार पर 10-अंकीय सूचकांक में मापा गया (उच्च उपयोग n=182, मध्यम n=178, निम्न n=56)। आश्रित चर को पीएम-किसान, मौसम, केसीसी, मंडी भाव, मृदा कार्ड, ई-गन्ना, डीबीटी व यूपीआई ज्ञान के आधार पर 10 अंकों में मापा गया (उच्च 8-10 अंक, मध्यम 5-7 अंक, निम्न 0-4 अंक)।

सारणी 3: संचार उपयोग तीव्रता एवं कृषि-आर्थिक जागरूकता का 3x3 क्रॉस-सारणीकरण

संचार उपयोग तीव्रता (X)	उच्च जागरूकता (8-10)	मध्यम जागरूकता (5-7)	निम्न जागरूकता (0-4)	कुल आवृत्ति (N)	संवर्ग प्रतिशत (%)
उच्च उपयोग (> 4 घंटे)	124 (68.13%) [fe = 77.88]	46 (25.27%) [fe = 70.88]	12 (6.59%) [fe = 33.25]	182	43.75%
मध्यम उपयोग (2-4 घंटे)	48 (26.97%) [fe = 76.16]	98 (55.06%) [fe = 69.32]	32 (17.98%) [fe = 32.52]	178	42.79%
निम्न उपयोग (< 2 घंटे)	6 (10.71%) [fe = 23.96]	18 (32.14%) [fe = 21.81]	32 (57.14%) [fe = 10.23]	56	13.46%
कुल महायोग	**178 (42.79%)**	**162 (38.94%)**	**76 (18.27%)**	**416**	**100.00%**

स्रोत: प्राथमिक समंक, तृप्ति सिंह (2026), पी.के. विश्वविद्यालय शोध प्रबंध। [fe = अपेक्षित आवृत्ति]

सांख्यिकीय परीक्षण परिणाम:

1. पियर्सन सहसंबंध: N = 416 पर r = +0.684 प्राप्त हुआ। छात्र टी-परीक्षण $t = r \cdot \sqrt{[/ (1 - r^2)]} = 19.06$ । चूंकि 19.06 क्रांतिक मान (3.310) से अत्यधिक बड़ा है, अतः सहसंबंध अत्यंत सार्थक है।
2. काई-वर्ग स्वतंत्रता परीक्षण: परिकलित $\chi^2 = 48.32$ प्राप्त हुआ। df = 4 पर p = 0.001 हेतु क्रांतिक मान 18.47 है। चूंकि $\chi^2 = 48.32 >> 18.47$, अतः शून्य परिकल्पना (H_{01}) निरस्त होती है और वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) पुष्ट होती है (ब्लैलॉक, 1979, पृ. 395)। यह सिद्ध करता है कि संचार साधनों का गहन उपभोग किसानों में कृषि-वित्तीय चेतना में प्रत्यक्ष वृद्धि करता है।

6. संरचनात्मक चुनौतियां, डिजिटल विभाजन एवं साइबर जोखिम

संचार क्रांति के साथ ग्रामीण समाज में गंभीर संरचनात्मक अंतर्विरोध भी उभरे हैं (वैन डिज्क, 2005, पृ. 19; वारशॉवर, 2003, पृ. 31):

1. अवसंरचनात्मक दुर्बलताएं एवं टैरिफ बोझ: नदी कछारों व सीमावर्ती गांवों में 63.46% (264 उत्तरदाता) कमजोर सिग्नल व कॉल ड्रॉप से पीड़ित हैं। आपातकालीन सेवाओं में नेटवर्क न मिलना घातक सिद्ध होता है। इसके साथ मोबाइल रिचार्ज दरों में 15-25% वृद्धि (₹299-₹349) ने 71.15% गरीब परिवारों के बजट पर चोट की है। ₹250-₹300 दैनिक मजदूरी वाले परिवारों में 3-4 फोनों पर ₹1,000-₹1,400 खर्च होना आय का 15-20% निचोड़ लेता है, जिससे डेटा की राशनिंग शुरू हो गई है।

2. डिजिटल निरक्षरता एवं नवीन बिचौलिया संस्कृति: व्यावहारिक साइबर सुरक्षा व परिचालन साक्षरता का स्तर 25% से कम है (50.96% स्वयं फॉर्म भरने में असमर्थ)। इसने सीएससी संचालकों के रूप में 'नए डिजिटल बिचौलियों' को जन्म दिया है, जो ₹15-₹30 के फॉर्म पर ₹100-₹300 तक अवैध वसूली करते हैं। AePS में बुजुर्गों के घिसे फिंगरप्रिंट्स के 'बायोमेट्रिक मिसमैच' से पेंशन व राशन रुकने की अमानवीय स्थिति बनती है।
3. साइबर वित्तीय अपराध: 59.62% ग्रामीणों को फर्जी बिल, लॉटरी व लोन ऐप के कॉल्स प्राप्त हुए। 16.35% (68 उत्तरदाता) वास्तव में ठगी के शिकार होकर ₹2,000 से ₹1.5 लाख गंवा चुके हैं। रिमोट एक्सेस ऐप्स से खाते खाली

Copyright @ 2026 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-16, Issue-03, 2026

कर दिए जाते हैं। विडंबना यह है कि 77.40% ग्रामीण राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा शिकायत प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे (एनसीआरबी, 2022, पृ. 412; आरबीआई, 2023, पृ. 34)।

7. नीतिगत संस्तुतियां एवं रणनीतिक रोडमैप

धरातलीय निष्कर्षों के आधार पर एक व्यावहारिक नीतिगत रोडमैप प्रस्तावित है:

1. शासन स्तर पर: 'भारतनेट 3.0' के अंतर्गत प्रत्येक मजरे व विद्यालय तक 50 Mbps मुफ्त वाई-फाई हॉटस्पॉट दिया जाए (मुखर्जी, 2021)। 'राष्ट्रीय ग्रामीण साइबर सुरक्षा मिशन' बनाकर पीएमजीदिशा में ओटीपी सुरक्षा का अनिवार्य प्रशिक्षण हो। AePS में वृद्धों हेतु मशीनों में आइरिस स्कैनर अथवा फेस रिकॉग्निशन अनिवार्य किया जाए (यूआईडीएआई, 2023)। सरकारी पोर्टल्स को 'भाषिणी' द्वारा भोजपुरी व स्थानीय बोलियों में वॉयस-सक्षम बनाया जाए।
2. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु: ट्राई के अंतर्गत ग्रामीण बीपीएल परिवारों हेतु न्यूनतम 1 GB दैनिक डेटा का रियायती 'ग्रामीण सोशल पैक' (अधिकतम ₹120-₹150 प्रतिमाह) दिया जाए। कछारी इलाकों में सौर ऊर्जा युक्त माइक्रो टावर्स लगाए जाएं तथा संदिग्ध कॉल्स की नेटवर्क स्तर पर स्वतः ब्लॉकिंग हो।
3. जिला प्रशासन व पुलिस हेतु: जिले के सभी 16 थानों में 'ग्रामीण साइबर सहायता डेस्क' बने। हेल्पलाइन 1930 तथा 'गोल्डन ऑवर' (प्रथम 2 घंटे) में खाता फ्रीज कराने का ग्राम सचिवालयों व कोटेदार दुकानों पर दीवार-लेखन प्रचार हो। सीएससी की नियमित जांच कर सरकारी रेट लिस्ट का प्रदर्शन सुनिश्चित कराया जाए।

8. उपसंहार एवं निष्कर्ष

यह समीक्षात्मक अध्ययन अकाट्य निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि डिजिटल संचार क्रांति ने देवरिया जनपद में ग्रामीण कृषि आर्थिकी और वित्तीय समावेशन को युगांतरकारी चेतना दी है। स्मार्टफोन ने सूचना के सामंती एकाधिकार को तोड़कर सीमांत किसानों को सीधे बाजार व राज्य का भागीदार बनाया है। मौसम पूर्वानुमान से बचत, ई-गन्ना से घटतौली की समाप्ति, डीबीटी से रिसाव का अंत, तथा यूपीआई व AePS द्वारा साहूकारी ब्याज से मुक्ति—ये अमर्त्य सेन के 'क्षमता विस्तार' और रोजर्स के 'नवाचार प्रसरण' के जीवंत प्रमाण हैं। तथापि, टैरिफ दरों के बोझ, कमजोर नेटवर्क, डिजिटल निरक्षरता तथा साइबर वित्तीय ठगी का समाधान न होने पर यह क्रांति नए डिजिटल विभाजन को जन्म देगी। अतः एक सुरक्षित, वहनीय और स्थानीय भाषा-सक्षम डिजिटल तंत्र ही समावेशी ग्रामीण विकास की अनिवार्य पूर्वशर्त है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अग्रवाल, बी. सी. (1981). SITE Social Evaluation: Results, Experiences, and Implications. अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र , अहमदाबाद.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. (2022). डिजिटल भारत प्रगति प्रतिवेदन 2021-2022. भारत सरकार, नई दिल्ली.

कूले, सी. एच. (1909). Social Organization: A Study of the Larger Mind. चार्ल्स स्क्रिबनेर्स संस, न्यूयॉर्क.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय. (2022). Evaluation Study of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

कोठारी, सी. आर., एवं गर्ग, जी. (2019). Research Methodology: Methods and Techniques (4th ed.). न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

गांधी, एम. के. (1942). Village Swaraj. नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद.

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग. (2023). Digital Governance in Cane Sector: Impact Analysis of e-Ganna App. उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ.

Copyright @ 2026 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-16, Issue-03, 2026

जनगणना कार्य निदेशालय. (2011). जिला जनगणना पुस्तिका: देवरिया (श्रृंखला 10, भाग XII-A). जनगणना कार्य महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

ट्राई. (2024). The Indian Telecom Services Performance Indicators: July-September 2023. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली.

ब्लैलॉक, एच. एम. (1979). Social Statistics. मैकग्रा-हिल, न्यूयॉर्क.

भारतीय रिजर्व बैंक. (2023). Report on Currency and Finance: Towards a Greener and Safer Digital Future. आरबीआई, मुंबई.

मुखर्जी, पी. (2021). The digital transformation of rural India: A policy analysis of BharatNet. Telematics and Informatics, 62, 101625.

मौसम विज्ञान विभाग. (2021). Gramin Krishi Mausam Sewa: Operational Guidelines and Impact Assessment in Eastern Uttar Pradesh. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

यूआईडीएआई. (2023). Biometric Authentication Guidelines for Financial Services and Public Distribution. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली.

रोजर्स, ई. एम. (1995). Diffusion of Innovations (4th ed.). द फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क.

रोजर्स, ई. एम. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). द फ्री प्रेस, न्यूयॉर्क.

लर्नर, डी. (1958). The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. फ्री प्रेस, ग्लेनको, आईएल.

वारशॉवर, एम. (2003). Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide. एमआईटी प्रेस, कैम्ब्रिज, एमए.

वित्त मंत्रालय. (2021). Seven Years of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: A Paradigm Shift in Financial Inclusion. वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली.

वैन डिज्क, जे. (2005). The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. सेज पब्लिकेशन्स, लंदन.

शुम्पीटर, जे. ए. (1934). The Theory of Economic Development. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, एमए.

सेन, ए. (1999). Development as Freedom. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड.

सिंह, टी. (2026). ग्रामीण जागरूकता में संचार क्रांति की भूमिका (देवरिया जिले के विशेष सन्दर्भ में). अप्रकाशित विद्यावाचस्पति (पीएच.डी.) शोध-प्रबंध, समाजशास्त्र विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.).

सिंह, टी., एवं बहादुर, जे. (2024). ग्रामीण पूर्वांचल में संचार क्रांति एवं सामाजिक परिवर्तन: एक समाजशास्त्रीय उपागम. शोध प्रभा, 49(1), 112-124.

सिंघल, ए., एवं रोजर्स, ई. एम. (2001). India's Communication Revolution: From Bullock Carts to Cyber Marts. सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

स्टिग्लिट्ज़, जे. ई. (2002). Information and the change in the paradigm in economics. American Economic Review, 92(3), 460-501.

आईआईटीएम. (2022). Lightning Location Network and Early Warning System: Technical Bulletin on Damini App Performance. भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे.

एनसीआरबी. (2022). Crime in India 2022: Cyber Crime Statistics. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

एनपीसीआई. (2024). Unified Payments Interface Monthly Metrics: Rural Penetration Study 2023-24. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई.

Copyright @ 2026 Author